II. विदेश में भारतीय संयुक्त उद्यमों और पूर्णतया स्वामित्व वाले सहायता प्राप्त उद्यमों की संख्या :

	भारतीय संयुक्त उद्यम		पूर्णतया स्वामित्व वाले सहायता प्राप्त उद्यम	
	चालू	कार्यान्वयन के अधीन	चालू	कार्यान्वयन के अधीन
31-12-90 को	159	55	42	12

केन्द्रीय सरकार की सेवाओं में सांप्रदायिक तत्व

1629. **श्री मोहम्मद अफजल उर्फ मीम अफजल :**

मौलाना ओबेदुल्ला खान आजमी :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बड़ी संख्या में इसके कर्मचारी साम्प्रदायिक संगठनों और संस्थाओं के सदस्य हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि केन्द्रीय सरकार के कई कर्मचारी साम्प्रदायिक संगठनों के साथ पोशीदा संबंध रखते हैं और वे सेवा निवृत्ति के पश्चात् उन दलों और संगठनों के सदस्य बन जाते हैं ;

(ग) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ; और

(घ) सरकार ने इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की है और निकट भविष्य में क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) से (घ) सरकारी कर्मचारियों को उन साम्प्रदायिक संगठनों तथा उनकी शाखाओं/संबद्ध निकायों का सदस्य बनने अथवा उनसे अपना संबंध रखने की मनाही है जिनके कार्यकलाप राजनीतिक स्वरूप के अथवा विध्वंसकारी हैं। किसी भी सरकारी कर्मचारी के खिलाफ जो इन संगठनों का सदस्य है अथवा इनकी गतिविधियों से अन्यथा रूप से जुड़ा हुआ है, अनुशासनिक कार्रवाई की जा सकती है। ये प्रतिबंध सेवा-निवृत्ति के पश्चात् सरकारी कर्मचारियों पर लागू नहीं होते हैं।

Manufacturing of arms by Ordnance factories for civil market

1630. SHRI SOM PAL:

SHRIMATI MIRA DAS:

Will the Minister of DEFENCE be pleased to state:

(a) whether Government are aware that small arms meant for supply to the civil market and being manufactured by the Ordnance factories are in short supply and that these are being sold in blackmarket at more than double the official price; and

(b) if so, whether Government would consider increasing the production of such arms to meet this shortage and eliminate blackmarketing?

THE MINISTER OF DEFENCE (SHRI SHARAD PAWAR): (a) Ordnance Factories' capacity for manufacture of small arms is, primarily, intended to cater to the requirements of the Defence, Paramilitary and Central/State Police Forces.